Question No. 104

(Un-Starred Question)

20 March 2023

INDEX OF INFORMATION

Sr. No.	Subject	Page No.
1	Reply of question No. 104 in English	2 - 3
2	Reply of question No. 104 in Hindi	4 - 5

Vidhan Sabha	10 copies
Chief Minister Secretariat	15 copies
Chief Secretary (in political Branch)	6 copies
Secretary/Chief Secretary	2 copies
Secretary/Governor	2 copies
DPR	4 copies
Finance Minister	1 copy
Finance Minister State	1 copy
Chief Parliamentary Secy.	1 copy
Parliamentary Secy.	1 copy
ACS Finance	1 copy

Vajra Model of Growth

104. Sh. VARUN CHAUDHRY (Mullana): Will the Chief Minister be pleased to state the action taken by the Government on the "Vajra Model of Growth" in State and the outcome thereof?

Answer

Manohar Lal, Chief Minister

Under "Vajra Model" five developmental forces have been envisaged for enhanced economic growth and human development, ease of living for citizens, lifting the poor and disadvantaged from all socio-economic groups, leveraging productivity through increased adoption of technology accompanied by employment and entrepreneurship. These five forces are:

i. *Samartha* Haryana - Reforms using technology;
ii. *Antyodaya* – the upliftment of the poorest of the poor,
iii. *SatatVikas* – Sustainable Development,
iv. *Santulit Paryavaran* - Environmental sustainability,
v. *Sahbhagita* - Government Community Participation

These five forces of development are the guiding principle for the Government. The Government implements a number of schemes for achieving the desired results under each force.

i. Samartha Haryana- Reforms using technology - Government has undertaken number of steps to promote IT in governance under the "Minimum Government Maximum Governance". Some of IT initiatives undertaken are 'Meri Fasal Mera Byora', 'Mera Paani Meri Virasat', e-kharid portal, IFMS, HALRIS and Privar Pahchan Patra (PPP) etc. These IT initiatives have enhanced the efficiency, effectiveness of governance and delivery mechanism.

ii. Antyodaya - For the upliftment of the poorest of the poor (family having an annual income of upto ₹1 lakh), a package of financial benefits under various schemes, customized to the requirement of each family, is being provided under Mukhyamantri Antyodya Parivar Utthan Yojana to the raise their family income to minimum ₹1.80 lakhs per annum. During 2022-23, 36,993 families have been sanctioned loans through Antyodaya Melas organized under the Yojana. In 2023-24, Government has proposed to fix a target to cover at least 2 lakh families in this income group and provide them with access to funding from banks for upto ₹1 lakh for which a sum of ₹ 2000 crores will be set aside in consultation with banks.

iii. *Satat Vikas* – Sustainable Development,

The Seventeen Sustainable Development Goals (SDG) provide a framework to achieve a better and sustainable future for all. This framework aims to reduce poverty and achieve economic growth while ensuring equity, peace, and security in the society. The Government has drawn up a Vision for achieving the SDG goals by 2030.

iv. Santulit Paryavaran - Environmental sustainability :

The Government has proposed to establish the Aravalli Safari Park over 10,000 acres of land in Gurugram and Nuh districts. The Divya Nagar Scheme *interalia* will provide for development of oxy-vans, city forests, large city parks and green spaces, city beautification, Inter University Centers and landscaping etc.

v. Sahbhagita - Government Community Participation

The State Government believes in participation of the people in formulation and implementation of schemes for welfare and development of citizens.

State Government has launched the 'Samarpan' portal to encourage such volunteers who are willing to serve the society and can become an essential part of social upliftment in Haryana by dedicating their time and effort towards social work. Volunteers will be connected through this portal, after which the services of volunteers including youth, retired employees will be taken in the field of education, skill development, sports, agriculture etc.

'Paudhagiri' campaign is one of the examples for increasing the green cover in the state through community participation.Under this campaign, 22 lakh students from class 6 to 12 of all government and private schools in Haryana will plant a sapling each during three months of monsoon - July, August and September.

Further, recent initiatives taken by the State Government to devolve funds, function and functionaries for empowerment of both urban and rural local bodies will further strengthen community participation in development efforts and delivery of programmes at the grassroot level in the State.

विकास का वज्र मॉडल

104. श्री वरुण चौधरी, (मुलाना) : क्या माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे कि सरकार ने राज्य में 'विकास के वज्र मॉडल' पर क्या काम किया है और उसके परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तरः

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

1. 'वज्र मॉडल' के अन्तर्गत आर्थिक विकास तथा मानव विकास, नागरिकों के जीवन की सुगमता, सभी सामाजिक–आर्थिक वर्गों के गरीबों और वंचितों के उत्थान, रोजगार और उद्यमिता के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से उत्पादकता का लाभ उठाने के लिए पांच विकास शक्तियों की परिकल्पना की गई है। ये पांच शक्तियां हैं :

   i. समर्थ हरियाणा–सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार,
   ii. अंत्योदय–सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान,
   iii. सतत विकास–सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
   iv. संतुलित पर्यावरण–पर्यावरणीय स्थिरता,
   v. सहभागिता–सरकारी–सामुदायिक भागीदारी

   विकास की ये पांच शक्तियां सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हर शक्ति के तहत सरकार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन करती है।

   i. **समर्थ हरियाणा–प्रौद्योगिकी के उपयोग से सुधार** – सरकार ने 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के तहत शासन में आई.टी. को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। शुरू की गई कुछ आईटी पहलें हैं – 'मेरी फसल मेरा ब्योरा', 'मेरा पानी मेरी विरासत', ई–खरीद पोर्टल, आई.एफ. एम.एस., हालरिस और परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) आदि। इन आई.टी. पहलों ने शासन की दक्षता व प्रभावशीलता और वितरण तंत्र को बढ़ाया है।

   ii. **अंत्योदय–** हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक है, के उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाकर कम से कम 1.80 लाख रुपये वार्षिक करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय लाभों का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अंत्योदय मेलों के माध्यम से 36,993 परिवारों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2023–24 के लिए, सरकार ने इस आय वर्ग में कम से कम 2 लाख परिवारों को कवर करने के लक्ष्य और उन्हें 1 लाख रुपये तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे।

iii. **सतत विकास – टिकाऊ विकास :**

सत्रह सतत विकास लक्ष्य (SDG) सभी के लिए बेहतर और सतत भविष्य की रूपरेखा प्रदान करते हैं। इस ढांचे का उद्देश्य समाज में समानता, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास हासिल करना है। सरकार ने 2030 तक SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विजन तैयार किया है।

iv. **संतुलित पर्यावरण – पर्यावरणीय स्थिरता :**

सरकार ने गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। दिव्य नगर योजना में अन्य बातों के साथ–साथ ऑक्सी–वन, शहरी वन, बड़े शहर पार्क व हरित स्थान, शहर के सौंदर्यीकरण, अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र और भू–दृश्य आदि का विकास किया जाएगा।

v. **सहभागिता – सरकार–समुदाय की भागीदारी :**

राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी में विश्वास करती है।

राज्य सरकार ने ऐसे स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'संपर्क' पोर्टल लॉन्च किया है जो समाज की सेवा करने के इच्छुक हैं और सामाजिक कार्यों के लिए अपना समय व प्रयास समर्पित करके हरियाणा में सामाजिक उत्थान का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जाएंगी।

'पौधागिरी' अभियान सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने का एक उदाहरण है। इस अभियान के तहत, हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के 22 लाख छात्र मानसून के तीन महीने –जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान एक–एक पौधा लगाएंगे।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए धन, कार्य व कार्यकर्त्ताओं के विकास के लिए हाल ही में की गई पहल राज्य में जमीनी स्तर पर विकास के प्रयासों और कार्यक्रमों के वितरण में सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करेगी।